के इस योजना से लाभान्वित होने की संभावना है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) आदिवासी उपयोजना जो 17 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों में चल रही है, का उद्देश्य व्यक्तिगत परिवार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आदिवासियों का विस्तृत विकास करना है। सातवीं योजना कार्यकारी दल ने जो योजना आयोग द्वारा नियुक्त किया गया था, आदिवासी उप-योजना नीति की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उप-योजना नीति के उद्देश्यों को पुनःनिर्धारित किया है । सातवी योजना के दौरान आदिवासी उप-योजना नीति के अन्तर्गत मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(i) कृषि, बागवानी, पशु-पालन, लघु उद्योग इत्यादि के क्षेत्र में लाभान्वित होने वाले परिवारों के उत्पादकता स्तर को उठाने के लिए परिवारोन्मुखी लाभकारी कार्यक्रमों को चलाना।

(ii) जनजातियों के शोषण को समाप्त करना।

(iii) शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा मानव संसाधनों का विकास।

(iv) मूल संरचना विकास।

(v) संवेदनशील जनजाति क्षेत्रों और समूहों का विकास।

(vi) जनजाति क्षेत्रों के पर्यावरण का दर्जा बढ़ाना।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 756 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता सहित लगभग 13,000 करोड़ रुपए के कुल व्यय की व्यवस्था है।

प्रधान मंत्री के दौरे के बाद, आदिवासी उप-योजना नीति की कार्य प्रणाली का पुनर्रीक्षण किया गया तथा राज्य सरकारों को योजनाओं के विशेष तौर से परिवारोन्मुखी कार्यक्रमों के प्रभावशाली प्रबोधन तथा मूल्यांकन के लिए कदम उठाने के लिए उचित रूप से निर्देश दिए गए हैं।

(ग) आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में राजस्थान के दो पूर्ण जिले तथा तेरह आंशिक जिले आते हैं जिनकी जनजाति जनसंख्या लगभग 27.00 लाख है। सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3,08,800 परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता देने का प्रस्ताव है। राजस्थान के लिए छठी योजना में 32.32 करोड़ रुपए के मुकाबले सातवीं योजना में 47.25 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता है।

पानी के टैंकर खरीदने के लिए राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

2066. **श्री भंवर लाल पंवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने पीने के पानी की समस्या हल करने के पेय जल के टैंकर खरीदने हेतु केन्द्र से हाल में कोई वित्तीय मदद मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी मदद दिए जाने की संभावना है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान राज्य सरकार ने पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए पेयजल टैंकरों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मांगी है। राज्य सरकार को 100 पेयजल टैंकर खरीदने की अनुमति दे दी गई है और वास्तविक लागत केन्द्रीय सहायता में से मुहैया की जाएगी।

राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय का खोला जाना

2067. **श्री भंवर लाल पंवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में ओपन कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की कोई योजना है; और

(ख) यह विश्वविद्यालय कहां और कब तक खोल दिया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) कृषि विश्वविद्यालय एक राज्य स्तर की संस्था है तथा राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किये गये अधिनियम के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है । राजस्थान में इस समय कोई भी अलग कृषि विश्वविद्यालय नही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् राज्य मे एक अलग कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से आग्रह करती रही है।

(ख) उपरोक्त के बारे में कानूनी स्थिति को ध्यान में रखकर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष कार्यवाही की जानी है ।

D.A.V.P. Advertisements to News-Papers Published from Calcutta

2068. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) what is the total value of DAVP advertisements given to the 'Statesman, Anandabazar Patrika, Jugantar, Amritabazar Patrika, Azkal, Basumati, Bartaman and Ganeshakti (Evening daily)' published from Calcutta during the years 1983, 1984 and 1985;

(b) what were the recommendations of the Bhabatosh Dutt Committee with regard to DAVP advertisement; and

(c) the extent to which those recommendations have been implemented.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL) : (a) The total value of the advertisements given to these newspapers by DAVP during the years 1983-84 , 1984-85 and 1985-86 (up to Spetember, 1985) was as under :—

Year	Amount
1983-84 . . .	19,57,803
1984-85 . . .	24,14,367
1985-86 . . .	10,96,297

(b) The main recommendations of the Bhabatosh Dutt Committee with regard to DAVP advertisements are given in the Statement I attached.

(c) The above mentioned recommendations have been implemented to the extent mentioned in the statement II attached.

Statement-4

The main recommendations of the Bhabatosh Dutt Committee with regard to Directorate of Advertising and Visual Publicity advertisements were as under :—

(1) The Government advertisements should be published in widely circulated papers particularly those which are in Indian languages. The advertisements regarding Family Planning, Agriculture Rural Development and the like should be issued in the papers which go to the rural areas.

(2) The rates offered by the government should be non-discriminatory. Government advertisements issued in an Indian Language paper should not earn less than is earned by the same advertisements appearing in an English language paper with the same level of circulation.

(3) Government policy encouraging the development of Indian languages should be extended to the Newspapers also. The policy of the government regarding allotment of and